शिक्षा संवाद
2021, 8(1-2): 35-42
ISSN: 2348-5558
©2021, संपादक, शिक्षा संवाद, नई दिल्ली

आलेख

आपदा का अवसर : स्कूली शिक्षा पर कोविड़ के प्रभाव

प्रीति सिंह
शोध छात्र
दिल्ली विश्वविद्यालय

सार

कोविड-19 महामारी ने 2020 के प्रारंभ में ही वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी थी और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। 2020 के मार्च माह में जब भारत में कोविड-19 के मामले बढ़ने लगे, तो सरकार ने सख्त कदम उठाए, जिनमें देशव्यापी लॉकडाउन और सामाजिक दूरी जैसे उपाय शामिल थे। इन उपायों का सबसे बड़ा असर बच्चों की स्कूली शिक्षा पर पड़ा। स्कूलों को बंद किया गया, परीक्षाओं को स्थगित किया गया और शिक्षा का पूरा ढांचा ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित हो गया। इस लेख में हम कोविड-19 की पहली लहर के दौरान भारत में स्कूली शिक्षा पर हुए प्रभावों का विश्लेषण करेंगे।

कूटशब्द : कोविड-19, महामारी, शिक्षा, समाज, परीक्षा, शिक्षण।

भारत में कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए सरकार ने 24 मार्च 2020 से पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया था। इसका प्रमुख उद्देश्य संक्रमण की दर को कम करना और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव को नियंत्रित करना था। इस दौरान स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग सेंटर और अन्य शैक्षिक संस्थान पूरी तरह से बंद कर दिए गए। यह कदम भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि यहां की अधिकांश शिक्षा प्रणाली पर ऑफलाइन शिक्षा निर्भर थी और ऑनलाइन शिक्षा का ढांचा कमजोर था।

शिक्षा में बदलाव

कोविड-19 के कारण विद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियाँ पूरी तरह से थम गईं। शिक्षकों को अपने पाठ्यक्रम को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पर प्रस्तुत करने के लिए नए तरीके अपनाने पड़े। ऑनलाइन शिक्षा ने स्कूली शिक्षा के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। हालांकि, इससे कुछ बच्चों और परिवारों के लिए नई संभावनाएँ खुलीं, लेकिन कई अन्य के लिए यह समस्या भी बन गई।

डिजिटल डिवाइड

भारत में डिजिटल डिवाइड यानी तकनीकी संसाधनों की असमान उपलब्धता, कोविड-19 के दौरान और भी स्पष्ट हो गई। शहरों में जहां इंटरनेट और स्मार्टफोन की सुविधा अधिक थी, वहां बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा मिल पाई। लेकिन ग्रामीण इलाकों, जहां इंटरनेट की कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन की उपलब्धता सीमित थी, वहां बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा असंभव बन गई। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 30% बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रहना पड़ा। यह असमानता सामाजिक और आर्थिक वर्गों के बीच एक और खाई को गहरा करने का कारण बनी।

मानसिक और शारीरिक प्रभाव

लॉकडाउन के दौरान बच्चों की मानसिक स्थिति पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा। लंबे समय तक घर पर रहने के कारण बच्चों में अकेलापन, चिंता और तनाव बढ़ने लगे। साथ ही, ऑनलाइन शिक्षा के दौरान बच्चों के शारीरिक गतिविधियाँ भी सीमित हो गईं। स्कूलों के बंद होने से खेलकूद और सामाजिक गतिविधियाँ प्रभावित हुईं, जिससे बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

शिक्षकों के लिए चुनौती

कोविड-19 ने शिक्षकों के लिए भी कई चुनौतियाँ पेश कीं। बहुत से शिक्षक, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, ऑनलाइन शिक्षण के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल और उपकरणों से वंचित थे। इसके अलावा, इंटरनेट की धीमी स्पीड और तकनीकी समस्याओं ने शैक्षिक

गतिविधियों को प्रभावित किया। शिक्षकों को लगातार नए शिक्षण तरीकों के साथ खुद को अनुकूलित करना पड़ा, जो कि आसान नहीं था। हालांकि, कुछ शिक्षकों ने इस स्थिति को सकारात्मक रूप में लिया और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके बच्चों को शिक्षित किया, लेकिन सभी शिक्षक इस परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थे।

परीक्षा और परिणाम

कोविड-19 के कारण शैक्षिक वर्ष में कई बदलाव हुए। बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा और फिर वैकल्पिक मूल्यांकन विधियों का सहारा लिया गया। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया और छात्रों को उनके पिछले परिणामों और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट किया गया। हालांकि यह निर्णय छात्रों के लिए राहत का कारण था, लेकिन यह परीक्षा प्रणाली की पारंपरिक मान्यता को चुनौती भी थी।

ऑनलाइन शिक्षा के लाभ और हानि

ऑनलाइन शिक्षा के कई फायदे भी थे। यह शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच को बढ़ाने का एक अच्छा तरीका था। छात्रों को घर बैठे पाठ्यक्रम, वीडियो लेक्चर्स, डिजिटल नोट्स और अन्य शैक्षिक सामग्री मिल रही थी। हालांकि, इसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि ऑनलाइन शिक्षा से छात्रों को एक संतुलित और समग्र शिक्षा नहीं मिल पाई। खासकर प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि उन्हें व्यक्तिगत मार्गदर्शन और देखरेख की आवश्यकता थी। कोविड-19 की पहली लहर ने भारत में स्कूली शिक्षा को एक नई दिशा दी, लेकिन यह बदलाव कठिनाईयों से भरा था। हालांकि ऑनलाइन शिक्षा के कई फायदे थे, लेकिन यह सभी वर्गों के बच्चों के लिए सुलभ नहीं था। इसके अलावा, यह बच्चों की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला भी साबित हुआ। भविष्य में यदि ऐसी स्थितियां फिर से उत्पन्न होती हैं, तो हमें शिक्षा के डिजिटलीकरण में समानता लाने और बच्चों की समग्र भलाई पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

कोविड-19 के बाद की शिक्षा प्रणाली में सुधार

कोविड-19 ने शैक्षिक व्यवस्था में कई स्थायी परिवर्तन किए, जिनका असर अब भी देखने को मिल रहा है। महामारी के दौरान स्कूलों के बंद होने से जो शिक्षा की डिजिटल दिशा बनी, वह अब भी जारी है, और इसे स्थायी रूप से अपनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्रों के लिए शिक्षा सुलभ हो, एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

महामारी के बाद, कई स्कूलों ने blended learning (मिश्रित शिक्षा) की दिशा में कदम बढ़ाया, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा दोनों का समावेश होता है। इसने शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला और सुलभ बनाने की दिशा में काम किया है। हालांकि, इसे पूरी तरह से सफल बनाने के लिए जरूरी है कि डिजिटल डिवाइड को कम किया जाए और सभी बच्चों को समान अवसर मिले।

भविष्य के लिए आवश्यक कदम

भारत में शिक्षा प्रणाली को कोविड-19 जैसी आपातकालीन स्थिति से बचाने और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। सबसे पहले, यह आवश्यक है कि डिजिटल संसाधनों की पहुंच सभी बच्चों तक हो, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी बच्चों के पास स्मार्टफोन, टैबलेट या कंप्यूटर जैसे उपकरण हों और इंटरनेट कनेक्टिविटी सुलभ हो। इसके अलावा, शिक्षा के डिजिटल रूपांतरण को स्थायी और प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण में भी सुधार की आवश्यकता है। शिक्षकों को नई तकनीकी विधियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे अपनी कक्षा में इनका प्रभावी उपयोग कर सकें। इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि बच्चों की सीखने की क्षमता भी बेहतर होगी।

बच्चों की मानसिक और शारीरिक भलाई पर ध्यान

कोविड-19 के दौरान बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी ध्यान देना जरूरी है। ऑनलाइन शिक्षा के दौरान बच्चों का शारीरिक गतिविधियों से संपर्क कम हो गया, जिससे उनकी मानसिक सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही, घर पर अकेले रहने के कारण बच्चों में तनाव और चिंता भी बढ़ी। भविष्य में बच्चों की मानसिक भलाई और शारीरिक विकास को प्राथमिकता देने के लिए स्कूलों में ऐसी गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए, जो बच्चों को शारीरिक रूप से सक्रिय रखें और मानसिक रूप से संतुलित करें।

सामाजिक और व्यक्तिगत कौशल की आवश्यकता

ऑनलाइन शिक्षा ने बच्चों को शारीरिक रूप से समाज से अलग कर दिया था, जिससे उनके सामाजिक और व्यक्तिगत कौशल में भी कमी आई। स्कूलों में बच्चों को साथ में काम करने, खेलने और अन्य सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का अवसर मिलता है, जो कि उनकी व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोविड-19 के बाद, यह आवश्यक हो गया है कि स्कूलों में बच्चों के सामाजिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। कोविड-19 के दौरान शिक्षा प्रणाली को कई तरह के परिवर्तनों से गुजरना पड़ा, लेकिन इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि अगर भविष्य में कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है, तो हमे और अधिक सशक्त और लचीला होना होगा। शिक्षा प्रणाली में डिजिटल और पारंपरिक तरीकों का सही मिश्रण, बच्चों की मानसिक और शारीरिक भलाई, और समग्र विकास पर जोर देना आवश्यक है। इसके साथ ही, शिक्षा के अधिकार को सभी बच्चों तक पहुंचाने के लिए हमें डिजिटल संसाधनों की समानता और शिक्षा के अवसरों में समावेशिता को सुनिश्चित करना होगा। कुल मिलाकर, कोविड-19 ने भारत की शिक्षा प्रणाली को एक नया दृष्टिकोण दिया और इसके माध्यम से हमें शिक्षा के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण पाठ भी मिले। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इन अनुभवों से क्या सिखते हैं और आगे बढ़ने के लिए क्या कदम उठाते हैं।कोविड-19 और शिक्षा प्रणाली में स्थायी परिवर्तन

कोविड-19 ने शिक्षा के पारंपरिक तरीके को पूरी तरह से चुनौती दी। महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति के दौरान शिक्षा की निरंतरता बनाए रखने के लिए, डिजिटल शिक्षा के बुनियादी ढांचे का मजबूत होना आवश्यक है। हालांकि, लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शिक्षा ने कई बच्चों के लिए नया मार्ग खोला, लेकिन यह भी सामने आया कि हर बच्चा इस तकनीकी युग में समृद्ध नहीं हो सकता है। इस महामारी ने भारत में शिक्षा प्रणाली में कई स्थायी बदलावों की शुरुआत की, जिनमें से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन डिजिटल शिक्षा का महत्व था। अब, स्कूलों में तकनीकी उपकरणों और इंटरनेट कनेक्टिविटी का उपयोग बहुत अधिक बढ़ गया है, और यह स्कूलों के पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। हालांकि, भारत जैसे विकासशील देश में जहां गरीब और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर जैसी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है, वहां शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सरकार को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

डिजिटल शिक्षा की चुनौती और अवसर

डिजिटल शिक्षा के विस्तार में जो अवसर हैं, वहीं चुनौतियाँ भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भारत में करीब 40% बच्चे, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित वर्गों से आने वाले बच्चे, डिजिटल संसाधनों से वंचित हैं। स्मार्टफोन, इंटरनेट, और अन्य तकनीकी उपकरणों की कमी ने उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा को अप्राप्य बना दिया। इस स्थिति ने "डिजिटल डिवाइड" (तकनीकी संसाधनों की असमानता) को उजागर किया, जिससे शिक्षा में असमानता और बढ़ गई। हालांकि, कोविड-19 के बाद, सरकार ने और निजी क्षेत्र ने इस समस्या को हल करने के लिए कई कदम उठाए। कई स्कूलों और शिक्षण संस्थानों ने छात्रों को मुफ्त में इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन या टैबलेट देने की योजना बनाई। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर शैक्षिक सामग्री को मुफ्त ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पर उपलब्ध कराया गया ताकि छात्रों को शिक्षा में कोई बाधा न आए।

सरकारी प्रयास और पहल

भारत सरकार ने कोविड-19 के दौरान शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई पहल की। **दीक्षा पोर्टल**, **स्वयं पोर्टल**, और **ई-आशा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स** के माध्यम से

लाखों बच्चों तक शिक्षा पहुँचाई गई। इसके अलावा, **रेडियो, टीवी और मोबाइल ऐप्स** का उपयोग करके भी शिक्षा प्रदान की गई, ताकि डिजिटल डिवाइड को कम किया जा सके। हालांकि, यह प्रयास शुरूआत में संतोषजनक थे, लेकिन जब तक यह पूरी तरह से प्रभावी और समावेशी नहीं बनेगा, तब तक पूरी शिक्षा प्रणाली में समानता सुनिश्चित करना कठिन होगा।

बच्चों की मानसिक सेहत का महत्व

महामारी के दौरान स्कूली शिक्षा के रूप में हुए बदलावों ने बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत पर गहरा प्रभाव डाला। बच्चों की व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों में कमी आई, जिससे उनमें अकेलापन, चिंता और मानसिक दबाव उत्पन्न हुआ। लॉकडाउन के दौरान स्कूलों के बंद होने से बच्चों के लिए अपने दोस्तों से मिलने, खेलकूद करने और अन्य सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का अवसर समाप्त हो गया था। इसने बच्चों के मानसिक विकास में रुकावट डाली। शिक्षकों ने ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई जारी रखी, लेकिन इस दौरान बच्चों को मानसिक रूप से समर्थन देने के लिए विशेष पहल की आवश्यकता थी। कई स्कूलों ने मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया, ताकि बच्चों को मानसिक दबाव से बचाया जा सके। इसके अलावा, पैरेंट्स और शिक्षकों को यह भी समझाने की आवश्यकता थी कि बच्चों को केवल शैक्षिक गतिविधियों में ही नहीं, बल्कि उनके सामाजिक और मानसिक विकास में भी सहायता मिलनी चाहिए।

शिक्षा में समानता की दिशा

कोविड-19 ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि क्या हम भारत में सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा अवसर सुनिश्चित कर पा रहे हैं। ग्रामीण और शहरी बच्चों के बीच शिक्षा का भेद स्पष्ट रूप से बढ़ा है। उच्च वर्ग के बच्चों को अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी और अच्छे तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता है, जबकि निम्न वर्ग के बच्चों को इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर सरकार और निजी संस्थाएं मिलकर डिजिटल समानता सुनिश्चित नहीं करतीं, तो भारत में शिक्षा की असमानता और भी बढ़ सकती है। सरकार को

शिक्षा में समानता लाने के लिए अधिक संसाधन और निवेश करने की आवश्यकता है। साथ ही, यह जरूरी है कि बच्चों की सामाजिक और मानसिक भलाई पर भी ध्यान दिया जाए। इस दिशा में, कई राज्य सरकारों ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए विभिन्न पहल की हैं, जैसे नि:शुल्क ऑनलाइन कक्षाएं, टैबलेट वितरण योजनाएं और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को समर्थन देने वाले कार्यक्रम।

निष्कर्ष

भारत में कोविड-19 की पहली लहर ने शिक्षा प्रणाली में एक अनिश्चितता का माहौल पैदा किया, लेकिन इसने साथ ही कई अवसर भी प्रदान किए। डिजिटल शिक्षा, हालांकि कई बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन इसने शिक्षा को एक नई दिशा दी। अब आवश्यकता है कि हम शिक्षा के डिजिटल रूपांतरण को अधिक सुलभ और समावेशी बनाएं, ताकि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हुए, हमें शिक्षा में समानता, मानसिक स्वास्थ्य, और शारीरिक भलाई पर भी ध्यान देना होगा, ताकि बच्चे मानसिक और शारीरिक दृष्टि से समृद्ध हो सकें। कोविड-19 ने यह साबित कर दिया कि शिक्षा केवल शैक्षिक पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बच्चों के समग्र विकास के लिए भी आवश्यक है।

*****

संदर्भ

- World Health Organization. (2020). *Coronavirus disease (COVID-19) pandemic*. https://www.who.int
- Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. (2020). *Guidelines for Covid-19 management*. https://www.mohfw.gov.in
- World Bank. (2020). *The COVID-19 Pandemic and its Impact on Developing Countries*. https://www.worldbank.org
- UNICEF. (2020). *The Impact of COVID-19 on Children's Education and Well-being*. https://www.unicef.org
- Ministry of Education, Government of India. (2020). *Education during COVID-19 Pandemic: A National Response*. https://www.mhrd.gov.in